भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2746

जिसका उत्तर बुधवार, 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है

न्याय कौशल

2746. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने समय और पैसा बचाने, त्वरित न्याय दिलाने तथा इसके लिए लंबी यात्रा से बचाने और अनावश्यक विलंब से बचने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विभिन्न असमानताओं को कम करने के लिए 'न्याय कौशल' नामक ई-रिसोर्स केंद्र के साथ-साथ वर्चुअल कोर्ट्स भी खोले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई है और इसके लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि स्वीकृत/व्यय की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : ई-संसाधन केन्द्र, न्याय कौशल बोम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर न्यायपीठ द्वारा आरंभ किया गया है । यह अक्तूबर, 2020 से कार्य कर रहा है, यह वकीलों और मुविक्कलों के लिए ई-फाइल करने, वर्चुअल सुनवाई करने और अन्य ई-न्यायालयी सेवाओं, आदि की प्रसुविधा प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त, यातायात चालानों से संबंधित मामलों का विचारण करने के लिए वर्चुअल न्यायालय भी आरंभ किए गए है । वर्तमान में 7 राज्यों/संघ-राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), चेन्नई (तमिलनाडु), बंगलुरु (कर्नाटक), कोच्चि (केरल), नागपुर (महाराष्ट्र), गुवाहाटी (असम) और पुणे (महाराष्ट्र) में नौ वर्चुअल न्यायालय हैं । तारीख 20 जनवरी, 2021 तक इन 9 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 41 लाख से अधिक मामले निपटाए गए हैं ।

(ख) : ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 के कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालय-वार जारी निधि की प्रास्थिति उपाबंध पर दी गई है ।

****

उपाबंध

न्याय कौशल के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2746 जिसका उत्तर 10.03.2021 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 के कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालय-वार जारी निधि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	**ई-न्यायालय चरण-2 के अधीन जारी की गई कुल निधि (करोड़ रुपए में)**
1.	इलाहाबाद	109.48
2.	आंध्र प्रदेश	1.96
3.	बॉम्बे	125.24
4.	कलकत्ता	37.09
5.	छत्तीसगढ	27.31
6.	दिल्ली	26.80
7.	गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश)	11.64
8.	गुवाहाटी (असम)	67.28
9.	गुवाहाटी (मिजोरम)	7.57
10.	गुवाहाटी (नागालैंड)	7.15
11.	गुजरात	72.82
12.	हिमाचल प्रदेश	10.27
13.	जम्मू और कश्मीर	18.98
14.	झारखंड	24.25
15.	कर्नाटक	65.38
16.	केरल	35.03
17.	मध्य प्रदेश	74.05
18.	मद्रास	70.15
19.	मणिपुर	8.52
20.	मेघालय	9.74
21.	ओडिशा	46.41
22.	पटना	55.82
23.	पंजाब और हरियाणा	54.13
24.	राजस्थान	67.80
25.	सिक्किम	6.81
26.	तेलंगाना	1.79
27.	त्रिपुरा	16.90
28.	उत्तराखंड	11.65
	कुल	**1142.30**

****